(c) The Reserve Bank of India has advised the commercial banks in the matter of meeting the cash credit requirements of the mills, on the basis of merits of individual applications and to the extent considered necessary.

(d) Due to a record production of sugarcane estimated at 180 million tonnes, some fall in the prices of sweetening agents was expected. Sugar production is expected to reach a record level of about 68 lakh tonnes and the price level is maintained at reasonable levels through judicious monthly releases. This will indirectly help gur and Khandsari prices too. In addition, the export of gur has been permitted and the ban on the forward markets in the commodity has also been lifted.

मत्स्य पालन के लिये पूर्वानुमति

6761. **श्री कुंभा राम आर्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें मत्स्य पालन के लिए पूर्वानुमति लेनी पड़ती है; और

(ख) इन राज्यों में ऐसी पाबन्दी लगाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) उपलब्ध जानकारी के आधार पर गैर सरकारी जलाशयों तथा तालाबों में मत्स्य पालन के लिए राज्य सरकारों से कोई पूर्व अनुमति उपलब्ध करने की जरूरत नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

राजस्थान को अनाज

6762. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सभी जिलों में भंयकर अकाल की स्थिति विशेष कर पश्चिम राजस्थान के जिलों में बदतर स्थिति को ध्यान में रखकर राजस्थान को विशेष मामले के रूप में अतिरिक्त अनाज दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1981 में और जनवरी, फरवरी और मार्च, 1982 में, पृथक-पृथक कितना गेहूँ और चावल दिया है और इस राज्य ने कितना गेहूँ और चावल मांगा था और यदि इतना नहीं दिया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता, विभिन्न राज्यों की सापेक्ष जरूरतों, बाजार में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर प्रत्येक मास के आधार पर खाद्यान्नों के आबंटन किए जाते हैं। 1979 से राज्य के कई एक जिले भिन्न-भिन्न परिमाण में सूखे से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार को जनवरी, 1981 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 6,000 मीटरी टन गेहूं आबंटित किया गया था। राज्य में चल रही स्थिति को देखते हुए, बाद के महीनों में आबंटन में वृद्धि कर दी गई थी और नवम्बर, 1981 तक 10,000 मीटरी टन से 20,000 मीटरी टन प्रतिमास के रेंज में गेहूं का आबंटन किया गया था। गेहूं के मासिक आबंटन को बढ़ाकर दिसम्बर, 1981 में 22,000 मीटरी टन कर दिया गया था और अप्रैल, 1982 से इसे और बढ़ाकर 24,000 मीटरी टन कर दिया गया है। खाद्यान्नों का जिलावार आन्तरिक वितरण राज्य सरकार द्वारा स्वयं किया जाता है।